भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-594
दिनांक 6 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

सौभाग्य योजना

594. श्री विद्युत बरन महतो:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में विशेषकर झारखंड में 'सौभाग्य योजना' के अंतर्गत घरों को विद्युत कनेक्शन प्रदान किए जाने की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) क्या सरकार देश भर में विद्युत आपूर्ति में सुधार लाने के लिए कोई विशेष परियोजना चला रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : भारत सरकार (जीओआई) ने अक्टूबर, 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों और शहरी क्षेत्रों में सभी इच्छुक गरीब घरों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करना है। सौभाग्य के तहत संस्वीकृत सभी कार्य सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं और यह स्कीम दिनांक 31.03.2022 को बंद हो चुकी है।

राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सौभाग्य अवधि के दौरान झारखंड राज्य के 17,30,708 घरों सहित लगभग 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया है।

(ख) : भारत सरकार ने जुलाई 2021 में वितरण क्षेत्र की प्रचालन दक्षता और वित्तीय स्थिरता में सुधार के लिए संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की। इस स्कीम के तहत 2.78 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें नुकसान कम करने के लिए अवसंरचना और स्मार्ट मीटरिंग कार्य शामिल हैं। भारत सरकार स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार आरडीएसएस के अंतर्गत सौभाग्य के दौरान छूटे हुए घरों के ऑन-ग्रिड विद्युतीकरण के लिए राज्यों को सहायता दे रही है। अब तक, वितरण यूटिलिटी द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आधार पर, 9,97,680 घरों के ग्रिड विद्युतीकरण के लिए 4,538 करोड़ रुपये की राशि के कार्य संस्वीकृत किए गए हैं। इसमें पीएम-जनमन (प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान) के अंतर्गत अभिचिन्हित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) से संबंधित घरों और जनजातीय घरों के साथ-साथ डीए-जेजीयूए (धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान) के अंतर्गत अभिचिन्हित सार्वजनिक स्थानों के लिए ग्रिड विद्युतीकरण कार्य शामिल हैं।

****